सहकारिता मंत्रालय **मांग संख्या 16**

1. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण (केंद्रीय प्रायोजित योजनाए)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में))	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
364	1. केंद्रीय प्रायोजित योजनाए का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और स्टाफ की क्षमता निर्माण	1.1. चालू वित्त वर्ष में कंप्यूटर/लैपटॉप आदि जैसे हार्डवेयर प्रदान किये गये PACS की संख्या।	11,700	1. केंद्रीय प्रायोजित योजनाए की कार्यक्षमता में वृद्धि और उनके कार्यों में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ाना	1.1 सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस)[1] और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)[2] को अपनाने वाले केंद्रीय प्रायोजित योजनाए की संख्या	11,700
		1.2. कार्यशील इंटरनेट/ ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले केंद्रीय प्रायोजित योजनाए की संख्या	11,700		1.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी स्वीकृत केंद्रीय प्रायोजित योजनाए के लिए ऑन-सिस्टम ऑडिट पूरे किए गए केंद्रीय प्रायोजित योजनाए की संख्या।	67,908
		1.3. तकनीकी प्रशिक्षण सत्र दिए गए **केंद्रीय प्रायोजित योजनाए** कर्मचारियों की संख्या	11,700		1.3. केंद्रीय प्रायोजित योजनाए द्वारा किए गए डे एंड्स का %।[3]	75
	2. कार्यशील केंद्रीय प्रायोजित योजनाए का संचालन और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोन का वितरण।	2.1. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ इंटीग्रेटेड ई-केंद्रीय प्रायोजित योजनाए की संख्या[4]	4,532	2. संस्थागत क्रेडिट तक आसान पहुंच और बिना बैंक वाले गांवों/इलाकों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार।	2.1. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दिए गए लोन की औसत राशि में बढ़ोतरी का %।	25[5]
					2.2. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दिए गए लोन की संख्या में बढ़ोतरी का %।	25[6]

[1] *सामान्य लेखा प्रणाली*

[2] *प्रबंधन सूचना प्रणाली*

[3] *हम केंद्रीय प्रायोजित योजनाए द्वारा किए गए दिन-समाप्ति कार्यों को एक परिणाम के रूप में प्रस्तावित करते हैं, जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाए अधिकारी लेखांकन त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा दिन-समाप्ति की गतिविधियों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में सक्षम हैं। हम वित्त वर्ष 2026-27 में प्रशिक्षित केंद्रीय प्रायोजित योजनाए अधिकारियों द्वारा लगभग 1.8 करोड़ (50000 * 365) दिन-समाप्ति कार्य संपन्न करने का लक्ष्य रखते हैं।*

[4] *लोन मैनेजमेंट सिस्टम और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बीच इंटीग्रेशन की कमी के कारण e- केंद्रीय प्रायोजित योजनाए के ज़रिए लोन मंज़ूर करना और देना अभी चालू नहीं है। नतीजतन, केंद्रीय प्रायोजित योजनाए लोन प्रोसेसिंग के लिए पुराने सिस्टम पर निर्भर हैं। फिलहाल, तमिलनाडु में इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, जिसमें कुल 4532 स्वीकृत PACS शामिल हैं और उम्मीद है कि 2026-27 की दूसरी तिमाही के आखिर तक इसमें प्रगति होगी।*

[5] *2025-26 की उपलब्धियों से 25% की बढ़ोतरी का लक्ष्य।*

[6] *2025-26 की उपलब्धियों से 25% की बढ़ोतरी का लक्ष्य।*